RAJYA SABHA

Friday, the 5th May, 1989/15th Vaisakha, 1911 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*161. [*The questioner (Shri Basudeb Mohapatra) was absent. For answer vide* cols. 37-38 infra].

*162. [*The questioner (Shri Santosh Kumar Sahu) was absent. For answer vide* col. 38 infra].

Average national rate of inflation for Agricultural Labour

*163. SHRI PRAMOD MAHAJAN :
SHRI SHANKER SINH VAGHELA :

Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) what was the average national rate of inflation (in consumer price index) for Agricultural Labour for the year 1988;

(b) whether it was for the different States and UTs and also in terms of the value of the Rup e during the each of the last three years: and

(c) what were the above figures in each of the three previous years; State-wise?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALAVIYA): (a) The average national rate of inflation in Consumer Price Index for Agricultural Labour for the year (Calendar) 1988 is 13.49 per cent.

(b) and (c) A staatement is laid on the Table of the House. [*See* Appendix CL, Annexure No. 57].

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Pramod Mahajan.

श्री प्रमोद महाजन : माननीय सभापति जी, खेतिहर मजदूर हमारे समाज जीवन का सबसे गरीब विभाग है। सरकार के उत्तर से पता चलता है कि अब औसत राष्ट्रीय मुद्रा-स्फीति की दर 9.8 प्रतिशत के आस-पास है खेती मजदूरों के लिए यह 13.49 है, लगभग डेढ़ गुना ज्यादा है । इसका अर्थ यह हुआ कि महंगाई की मार सब से अधिक खेतिहर मजदूर पर पड़ती है । खेतिहर मजदूर का दूसरा दुर्भाग्य यह है कि अन्य मजदूरों की तरह से संगठित नहीं है जो सरकार की या मालिक की नाक दबाकर अपने काम का उचित दाम वसूल कर ले । ऐसी स्थिति देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि मुद्रा-स्फीति की इस मार से खेतिहर मजदूर को बचाने के लिए केन्द्र सरकार किस प्रकार की योजना कर रही है ?

श्री राधा कृष्ण माल्वाय : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो पूछा कि राष्ट्रीय स्तर पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 9.8 उन्होंने कहा, वह इससे भिन्न है एग्रीकल्चरल लेबर का जो प्राइस इंडैक्स है जैसा कि मैंने अपने स्टेटमेंट में बताया वह 13.49 परसेंट है । रोकने के जो उपाय हैं वे इस प्रकार से हैं कि तीन साल से लगातार हमारे इस देश में सूखा पड़ता आया है और जो हमारा स्टाक था एग्रीकल्चरल लेबर को सब प्रकार की सुविधाएं देने के लिए अनाज वगैरह की वह 1987 में टोटल 19.536 मिलियन टन था, 1988 में 9.427 मिलियन टन हमारा स्टाक था जिसमें गेहूं, चावल और कोर्स ग्रेन वगैरह जो आते हैं और 1989 में आज हमारा स्टाक सिर्फ 7.387 हो गया । इसका मतलब है कि 1987 में हमारे पास बफर स्टाक ज्यादा था और आज 1989 में यह कम है । हमने फेयर प्राइस दुकानों के जरिए विलेजेज में जो हमारे खेतिहर मजदूर हैं, जो दूर दूर हैं उनको सुविधा देने के लिए अनाज की कमी न आए, उसके लिए वहां पर यह अनाज पहुंचाया । दूसरा आपने पूछा कि सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए रोकने के लिए तो सरकार ने कई प्रकार के उपाय किए कंज्यूमर प्राइस जो

इसका रेट बढ़ा उसको रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाए रखने के लिए गोदामों में से ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाद्यान्न रिलीज किया गया । साढ़े तीन लाख उचित मूल्य की दुकानें हमारी पूरे देश में हैं जिनके माध्यम से हम उनको खाद्यान्न देते हैं । तीसरा है, जो हमने आयात किया खाद्यान्न दो मिलियन टन और खाद्य तेल सोलह लाख टन वर्ष 1988 में ताकि मर्केट भाव उसका न बढ़े । हमने ग्रामीण रोजगार चलाकर लोगों को रोजगार दिलाया, जैसे एन० आर०ई०पी० और आर०एल०ई० जी०पी० के माध्यम से । उपरोक्त कारणों से हमारे देश में भूख से एक भी व्यक्ति नहीं मरा । श्रम मंत्रालय के द्वारा की गई जं. कार्यवाही है, पूर्व में न्यूनतम मजदूरी की दरें पांच वर्ष में कई बार रिवाइज की जाती थीं, अब यह दरें दो वर्ष में एक बार या महंगाई का 50 प्वाइंट बढ़ने पर, जो भी पहले हो करने का निर्णय श्रम मंत्री के सम्मेलन में नवम्बर 1988 में लिया गया है ।

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, सरकार का यह दावा है कि भूख से एक भी व्यक्ति नहीं मरा । वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से यह सच हो सकता है क्योंकि भूख से मरना यह मरने का कारण किसी डाक्टर के द्वारा बताना संभव नहीं है । आदमी जब भूखा होता है तो फिर वह बीमारियों का शिकार होकर मरता है पोस्टमार्टम में केवल भूख का कारण सामने नहीं आता । दुर्भाग्य से मजदूरी की जो स्थिति है, उस स्थिति का वास्तविक पता सरकार को नहीं है । केवल खाद्यान्न, यह बात नहीं है, यह जो खेतिहर मजदूर, जो सबसे अधिक गरीब तबका है और जो महंगाई का डेढ़ गुना मार खा रहा है, इसके लिए सरकार की ओर से किसी विशेष योजना की बात मंत्री महोदय ने नहीं कही है । मैं इसमें दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार संगठित मजदूरों की मुद्रास्फीति बढ़ते ही मजदूरी बढ़ाने का प्रावधान है, क्या उसी प्रकार खेतिहार मजदूरों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत जो वेतन दिया जाता है, उसकी भी मात्रा मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ाने का प्रावधान उसमें है ? यदि है, तो गत तीन वर्षों में जैसे मुद्रास्फीति बढ़ी उस प्रकार क्या इनका वेतन बढ़ा ? और यह वेतन देने की प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्था सरकार ने किस प्रकार से की है ?

श्री राधाकृष्ण मालवीय : सर, हमारा जो बेस ईयर है वह 1960–61 चल रहा है और उसके आधार पर मिनिमम वेजेज फिक्स हैं । यह एक बहुत लंबा-चौड़ा विषय है, मगर फिर भी मैं इसकी जानकारी माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं । कृषि श्रमिकों के लिए प्राइस-इंडैक्स तय करने के लिए इसका सर्वे किया गया । नेशनल सेंपल सर्वे आर्गेनाइजशन के द्वारा और वह 1983–84 में कंपलीट हुआ । हमारा प्रयास है हम इसका बेस ईयर 1986–87 करने जा रहे हैं ।

श्री प्रमोद महाजन : इसमें प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री राधाकृष्ण मालवीय: सुन तो लीजिए । उसका काफी-लंबा-चौड़ा मामला है, प्राइस फिक्स करना आसान खेल नहीं है । आपने तो पूछने को झट पूछ लिया उसके लिए सब ओर से जानकारी ली जाती है ।

श्री प्रमोद महाजन : मैंने तो झट से पूछ लिया, उत्तर देने में आपको तकलीफ हो रही है, मैं समझ सकता हूं ।

श्री राधा कृष्ण मालवीय : आप को पूछने का अधिकार है । तो 1986–87 बेस ईयर लागू करने का विचार सरकार कर रही है, विचार चल रहा है । कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स और एग्रीकल्चर प्राईस इंडैक्स दोनों में समानता बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग हैं । कंज्यूमर्स की प्राइस इंडैक्स जो शहरों में रहते हैं उनकी अलग है और एग्रीकल्चर लेबर की अलग है, दोनों ही अलग हैं ।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, जो मैंने नहीं पूछा, उसका उत्तर मुझे नहीं चाहिए । मैंने केवल एक प्रश्न पूछा था कि जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती जाती है, उसके अनुसार खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने

का कोई प्रावधान है क्या ? और उसकी व्यवस्था क्या है ? बाकी मुश्किलें आपको हैं, वह बाद में हल कर लें । मुझे इतना बता दीजिए, गत वर्ष के मुकाबले अगर मुद्रास्फीति इस वर्ष के हिसाब से एक पर-सेंट बढ़ गई तो क्या उनकी मजदूरी बढ़ती हैं ? और उसका क्या हिसाब आप करते हैं ?

श्री राधा कृष्ण मालवीय : सर, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है, जैसा मैंने पूर्व में कहा है कि मजदूरी पहले पांच वर्ष में रिवाइज होती थी, अब हाल में यह निर्णय लिया गया है कि दो वर्ष में मिनि-मम वेजेज रिवाइज हों, या मंहगाई 50 पाइंट पर, जो भी जल्दी हो जाय । अगर महंगाई 50 पाइंट बढ़ गई तो मजदूरी रिवाइज होगी या दो वर्ष में कंपलसरी है । इसके लिए मई, 1989 में वेरियस स्टेट्स से इसकी सारी जानकारी आएगी । हमने जो श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, उसमें इसको 11 रुपए फिक्स कर दिया कि 11 रुपए से कम रेट नहीं होगा । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, मैंने पूछा कि गत वर्ष मुद्रास्फीति कितनी थी, इस वर्ष कितनी है ? गत वर्ष वेतन कितना था, इस वर्ष कितना है ? तो आंकड़ों से हमको भी पता चलेगा, उनको भी पता चलेगा । यह साधारण प्रक्रिया है, कोई मुश्किल नहीं है . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सभापति : आपने अब बढ़ाया है । पहले कितना था ? बस यह बता दें । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री राधा कृष्ण मालवीय : सर, पहले तो अलग-अलग स्टेट्स का यह न्यूनतम मजदूरी फिक्स करने का काम राज्य सरकारों का है . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सभापति : नहीं, नहीं । मिनिमम वेज पहले क्या फिक्स किया था इस साल क्या फिक्स किया ? . . . (**व्यवधान**)

श्री राधा कृष्ण मालवीय : सर, जैसा मैंने कहा कि मिनिमम वेज फिक्स करने का काम हमारी राज्य सरकारों का है . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सभापति : इनका सवाल सिर्फ यह है कि इस साल आपने कितना फिक्स किया और पिछले साल क्या था ? . . . (**व्यवधान** . . .)

श्री राधाकृष्ण मालवीय : सर, हर स्टेट का अलग-अलग वेज होता है । हम फिक्स नहीं करते. . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सभापति : आपने 11 रुपए बोला है न । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री प्रमोद महाजन : अभी आपने जो 11 रुपये बोला, वह किसका था ? . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री राधा कृष्ण मालवीय : सर, 11 रुपए का तो, हमने श्रम मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया और उसमें अनुरोध किया कि इस देश में 11 रुपए से कम न हो । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सभापति : अभी हुआ नहीं है ? . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री राधा कृष्ण मालवीय : लागू कर दिया है । स्टेट से आ रही है और मई के एंड तक सब स्टेटस से हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी कि हम मिनिमम वेज 11 रुपए तक देंगे और अगर माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो मैं हर स्टेट का पूरा ब्यौरा आपको दे दूं । आन्ध्र प्रदेश में . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सभापति : यह स्टेट सबजेक्ट है ।

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, I am aware that the minimum wages in different States are different. I do understand that the Central Government can only give guidelines, and the fixing authority is the State Government concerned. But the statement given is really surprising. According to that, the rate of inflation in rsepesct of Andhra Pradesh is 16.5 while the value of the rupee is

0.17, that is 17 naye paise. On the other hand, in respect of U.P., the inflation is 18.8 and the value of the rupee is 13 naye paise. There are various States in between. I am not going into them. These are the two extremes. The unorganised labour suffer this inflation. This is the farm-labour community which is not an organised unit as in the urban sector for whom D.A. is linked to a variety of products or product-mix. Being unorganised, the farm labour is the worst-affected in the country. Their wages are not monitored to the authority fixing wages. Whatever has been fixed is paid on the farm itsef. It seems that the value of the rupee, in general terms, is roughly between 13 and 14 naye paise. Considering the value of the rupee which is between 13 and 14 naye paise and the inflation in the two States which is around 16.5, will the Minister be pleased to say whether this affects the consumption pattern of a family and whether this neutralises the effect of the wage given? That is my first question. Secondly, as I said, the State Governments are lacking in monitoring instruments. That is why the unorganised farm-labour is always at the receiving end. Added to this, if there is a drought, then, only God can help them. I want to know whether there is any proposal with the Government of India to monitor these two aspects of the farm-labour community as regards the standard of their living.

श्री राधा कृष्ण मालवीय : महोदय, जैसा कि माननीय सिंह ने बताया, हमारा बेस 1960–61 का है और रेट आफ इनफ्लेशन हमारा आल इण्डिया वाइज 13.49 प्रतिशत, या लगभग 13.5 प्रतिशत है, रुपए की वैल्यू हमारी आज 14 प्रतिशत है । रुपए की वैल्यू कम हुई और मुद्रास्फीति की दर जो बढ़ी-घटी उसकी स्टेटवाइज फिगर मेरे पास हैं कि इस इस में रुपए की वेल्यू घटी और इफ्लेशन इस प्रकार से हुआ । जैसा कि आपने कहा, असंगठित मजदूरों पर इसका ज्यादा असर पड़ता है, इसके लिए हमारे पास एक एजेन्सी है । अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो सीधे स्टेट गवर्नमेंट को कहा जाता है कि यहां पर महंगाई बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए प्रयास कीजिए ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि जो यह चार्ट आपने पेश किया है, इसमें मुद्रास्फीति जो बढ़ी है उसमें वैस्ट बंगाल में 6.1 प्रतिशत 1987–88 में थी जो 7.5 प्रतिशत 1988–89 में हुई । राजस्थान में 4.5 से बढ़ कर 17.1 यानि चार गुने से अधिक हो गई । उत्तर प्रदेश में सवा दु गुना बढ़ी । पंजाब वगैरह में सवा दो गुना बढ़ी । उड़ीसा में सवा दो गुना बढ़ी और असम में 8 से बढ़कर 9.6 हो गई । तो इसका कारण क्या है कि कहीं चार गुना या कहीं सवा दो गुना और कहीं 10, .8 या .5 प्रतिशत बढ़ी । किन वजूहात से इतना अन्तर इन प्रदेशों में है ? अगर आप केरल को देखें तो केरल का औसत 8.3 से 7.3 यानी करीब एक प्रतिशत घट गया है । तो इसका कारण बतायेंगे कि किन कारणों से उनमें ज्यादा है और इनमें कम है जब कि केरल में 1973 में यह 21 प्रतिशत था जो 1988 में घटकर 7.3 प्रतिशत हो गया । इसको क्या आप स्पष्ट करेंगे ?

श्री राधाकृष्ण मालवीय : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने बताया कि रुपए की इन्फ्लेशन दर प्रान्त में अलग-अलग इस वजह से हुई कि वहां मार्केट वेल्यू या वहां आवश्यकताएं अलग अलग रहती है । स्टेटवाइज उसकी फिगर्स मैंने दी है । तीन साल से लगातार हमारे देश में सूखा पड़ रहा था । उस वजह से भी किसी प्रान्त से किसी चीज की सप्लाई कम या ज्यादा हुई जिससे भाव बढ़े । इस प्रकार अलग अलग स्टेट के आंकड़े अलग हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : लेकिन मान्यवर यह चार गुना कैसे हो गई ? . . . (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI JAGDISH TYTLER): I think this question relates to the Finance Ministry, not Labour Ministry.

SHRI A. G. KULKARNI: This question should have been addressed to the Ministry of Finance.

श्री सभापति : मैं भी यही सोच रहा था कि यह प्रश्न इनसे न पूछें तो बेहतर है . . .

श्री वीरेन्द्र वर्मा : किसी भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया ।

SHRI A. G. KULKARNI: Sir I would like to submit that the question should have been addressed to the Ministry of Finance. The Labour Minister is.....

SHRI LAL K. ADVANI: Innocent!

SHRI A. G. KULKARNI:.... is not knowing anything on this because the rate of inflation, money value, and such other questions are involved. He cannot answer all these. The question has been wrongly addressed to him. So, this should not be discussed at all now.

MR. CHAIRMAN: Now, the question put by everybody is this: Why is the rate of inflation different in different States and in different years? Everbody in the House knows that this is not the question which is to be answered by him. Members are interested only in what the rate of inflation is and how it can be neutralised and that is the job of the Labour Ministry. But the causes for inflation and other such things do not come within the purview of the Labour Ministry.... (*Interruptions*).... The question has been asked of the Labour Ministry and, under the circumstances, the Laubour Ministry cannot say about The causes of inflation and all that; they are indifferent to it . . . (*Interruptions*)...

SHRI PRAMOD MAHAJAN: The Minister is in labour!

MR. CHAIRMAN: The Labour Ministry has to try and see how to neutralise it and there is the question of DA and the question of urban areas and so on and so forth. Here again they have to try to raise the wages and persuade the State Governments to increase the wages of the agricultural labour. To that extent they come into the picture. But the causes of inflation and other things, you will all agree, are not the subject concerning the Ministry of Labour....(*Interruptions*) . . .

SHRI A. G. KULKARNI : Sir may I say one thing? He is the Minister for Labour, but he cannot produce anything. So, let him remain like that.

MR. CHAIRMAN: He is the Minister of Labour and will have to solve labour problems. He is not in labour...(*Interruptions*)...

PROF. C. LAKSHMANNA : Sir, the answer that is given, if it is not properly understood, is likely to create certain problems. All that we ask for is... (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Bir Bhadra Pratap Singh.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH : Sir, this is a pure and simple labour problem and proper realisation should be there about two basic factors. Basic realisation should be there that as compared the wage of labour in the organised sector, wages in the agricultural sector by and large in the country are lower. Now, the second point is whether the lower wage is still adversely affected by the increase in inflation in the country.

MR. CHAIRMAN: What is your question ?

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: I am coming to my question. The Reserve Bank of India has also reported on this matter. I expect the honourable Minister to have taken note of the structure of agricultural labour wages in the country. Therefore, may I know what corrective or remedial measures are being taken by the Government in pursuance of the recommendations made in the report submitted by the Reserve Bank of India?

MR. CHAIRMAN: He has referred to the Labour Conference which has recommended a higher wage. These are the efforts they are making and they are trying to persuade the State Governments to fall in line. What do you want to know more now?

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: It is only after the report of the Reserve Bank of India that the two basic factors have been realised. So, in view of the report of the Reserve Bank of India,....

MR. CHAIRMAN: The report of the Reserve Bank of India is there. What do you want the Labour Minister to do?

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: I want to know whether the Labour Minister has taken note of that report and, if so, what corrective or remedial measures he proposes to take in accordance with the recommendations made in that report.

SHRI A. G. KULKARNI: The Ministry of Finance will take care of that.

MR. CHAIRMAN: The remedial measure is to increase the wages of agricultural labour.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: I am talking about that only.

MR. CHAIRMAN: He has already said it and he has said that they have recommended a rate of Rs. 11/- or something like that. Yes, Mr. Lakshmanna.

PROF. C. LAKSHMANNA: The answer given....

MR. CHAIRMAN: You are a Professor of Economics?

SHRI DIPEN GHOSH: He teaches politics.

PROF. C. LAKSHMANNA: My subject is sociology. Let the Minister look at the figures for Andhra Pradesh and the look at the figures for all-India. Obviously there has to be some difficulty or some confusion here. From 1983 onwards, the figures are 2·9, 5·7, 3·1, 3·0, 5·9 and 16·5. Then come to the rupee value. It is ·24, ·22, ·22, ·21. 0.20, and .17. Look at the all-India figure. It is 13·49 and the rupee value is ·14. Obviously there is something wrong with the statistics.

MR. CHAIRMAN: Rupee value is greater in Andhra Pradesh.

PROF. C. LAKSHMANNA: That is what I am saying. If the inflation rate is 16·5, obviously the value of the rupee should have been less than ·14. Therefore, I feel that the figure for Andhra Pradesh is incorrect. It might be perhaps 6·5. If it is 6·5, then perhaps ·17 can be the rupee value. If it is 16·5, I would like to know from the hon. Minister..... (*Interruptions*) If the Chairman permits, I will explain the whole thing. That is not the problem.

SHRI A. G. KULKARNI: The Public Distribution System is not working properly. The Andhra Pradesh Government is at fault.

PROF. C. LAKSHMANNA: What are the items that have been

taken into consideration in calculating inflation for agricultural labour and what is the minimum wage that is available in Andhra Pradesh How do you explain 16.5 as the inflation rate and .17 as the rupee value in terms of Consumer Price Index.

श्री राधाकृष्ण मालवीय : महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, वैसे ये फीगर्स कलेक्ट करना फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है । हम मजदूरों को वेजज मिले या नहीं मिले, इसके लिये हैं। हमारा प्रयास मजदूरों को उचित मजदूरी दिलाने से रहता है । . . . **(व्यवधान)**

PROF. C. LAKSHMANNA : Then you say 'subject to correction'. I will not proceed further.

श्री राधाकृष्ण मालवीय : आप नोटिस देंगे तो मैं जांच करवा कर आपके पास भिजवा दूंगा । जैसे इन्होंने बताया है, रेट आफ इंफलेशन में और वेल्यू आफ रुपये में आंध्र प्रदेश में कुछ डिफरेंस है और आल इंडिया बेस, यह बताया । यह हर स्टेट का अलग अलग है । इसमें आल इंडिया बेसिस का 13.49 और रुपये की वेल्यू 0.14 है । आंध्र में जो बताया है, जैसे मैंने कहा, हर स्टेट का अलग अलग है । यह एवरेज है । पूरे 15 राज्यों के समूह का एवरेज है आल इंडियावाइज । आंध्र का जो है वह अलग है । आंध्र का इसमें रेट आफ इंफलेशन 1986 में 3.7, 1987 में 5.09 और 1988 में 16.5 है । जैसे मैंने बताया है, तीन साल का जो सूखा पड़ा उसका इस रेट पर असर पड़ा है ।

PROF. C. LAKSHMANNA : The question of drought does not come here. We are talking about the juggalry of figures here.

MR. CHAIRMAN : Question No. 164.

SHRI DIPEN GHOSH : Sir, yesterday you did not allow me to raise any supplementary on the ground that some of my party Members had raised supplementaries. None has been allowed today.

MR. CHAIRMAN: The point is that I have got limited time.

SHRI DIPEN GHOSH : Does that limit of time not apply to others?

MR. CHAIRMAN: Mr. Ghosh, it is my right to determine.

SHRI DIPEN GHOSH: I know, Sir. I am not challenging your right.

MR. CHAIRMAN: I have done it with the best of my ability and in all sincerity.

SHRI DIPEN GHOSH : I am not challenging your right, Sir. I wanted to raise a supplementary.

MR. CHAIRMAN: I have said that I am moving to another question.

SHRI DIPEN GOSH : At least you should see.

MR. CHAIRMAN: I have seen. I have got names with me. I have to decide as to how many supplementaries and by whom I have to permit. This is my right and you, as an old Member, know that I am within my right to call another question.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : चेयरमैन साहब, मंत्री जी जवाब ठीक से नहीं दे सके इस लिये इसको फाइनेंस में भिजवा दीजिये ।